(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कु० सैलजा): (क) 1965 में इसके प्रारम्भ से ही भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला ने अभी तक 194 खण्ड प्रकाशित किए हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

(I) विनिबन्ध	—	95
(II) सेमिनारों की कार्रवाई	—	45
(III) अतिथि प्रोफेसरों द्वारा लेक्चर	—	23
(IV) प्रासंगिक पेपर	—	19
(V) पुनः मुद्रण	—	12

इस समय 12 पुस्तकें प्रकाशनाधीन है।

(ख) पिछले छः वर्षों के दौरान अध्येताओं द्वारा आरम्भ की गई शोध परियोजनाओं का ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है [देखिए परिशिष्ट 173, अनुपत्र सं० 126]

(ग) व (घ) संस्थान ने 1994-95 के दौरान राष्ट्रीय अध्येता के रूप में अपनी पसंद के विषय पर कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हिन्दी लेखक डा० भीष्म साहनी को आमंत्रित किया था। डा० प्रेम सिंह को "स्वतंत्रोत्तर हिन्दी व बंगला उपन्यासों में क्रांति व इसकी राजनीति के विचार" पर कार्य करने हेतु तीन वर्षों की अवधि के लिए शोध अध्येतावृति दी गई थी।

Functioning of UGC Regional Offices

5692. SHRI GUNDAPPA KORWAR: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether all the regional Offices of the University Grants Commission have started functioning; and

(b) if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KM. SELJA): (a) and (b) According to the information furnished by the University Grants Commission, the Regional Offices of UGC at Hyderabad, Pune, Bhopal and Ghaziabad have started functioning. The Regional Offices at Guwahati and Calcutta are likely to become functional soon.

रोजगारोन्मुख शिक्षा

5693. **श्री अनन्त राम जायसवाल:**
श्री सत्य प्रकाश मालवीय:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्कूल स्तर पर कम्प्यूटर की आधारभूत जानकारी सहित रोजगारोन्मुख शिक्षा संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्रियान्वयन और रोजगारोन्मुख शिक्षा पर कितनी धनराशि खर्च की जायेगी और उक्त प्रस्ताव के क्रियान्वयन तथा पूरा होने की समय अवधि क्या होगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कु० सैलजा): (क) और (ख) शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने की दृष्टि से, भारत सरकार ने फरवरी 1988 में माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना आरंभ की थी। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 1995-96 के लिए 82.00 करोड़ रु० की राशि निर्धारित की गई है। यह एक वर्तमान योजना है तथा इस समय संपूर्ण देश के 6280 स्कूलों में 18055 व्यावसायिक कक्षाएं अनुमोदित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 150 विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं जिसमें कम्प्यूटर पाठ्यक्रम भी शामिल हैं।

इसके अलावा, 1984-85 में आरंभ की गई "स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता तथा अध्ययन" (क्लास) नामक एक अग्रगामी योजना को वर्ष 1993-94 में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में संशोधित कर दिया गया था। इस संशोधित योजना के अन्तर्गत चुनिन्दा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा XI तथा XII के सभी छात्रों के लिए कम्प्यूटर शिक्षा में अध्ययन अनिवार्य